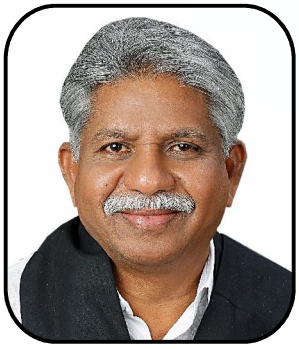

SHRI MANDA KRISHNA MADIGA

Shri Manda Krishna Madiga is a distinguished social activist and politician from Telangana, who pioneered the mass movement for social justice for the Madiga community and other marginalised groups, paving the way for the landmark judgement on SC Sub categorisation.

2. Born on 7th July, 1965, in New Shayampet, Hanamkonda, Telangana, in the Madiga community, traditionally associated with leatherwork and other marginalized professions. He experienced first-hand, the challenges and systemic discrimination faced by his community. In the early 1980s, he emerged as a prominent anti-caste and social activist in Warangal, Telangana confronting dominant caste individuals who oppressed lower castes. He chose to pursue the rights of marginalized Dalit communities through legal and peaceful means.

3. Disillusioned by the broader Dalit movement's inability to address the specific grievances of the Madiga and other sub-castes, Shri Madiga recognized the need for a focused movement, which led to the inception of the Madiga Reservation Porata Samiti (MRPS) in 1994. The MRPS was established with the primary objective of advocating for the sub- categorization of Scheduled Castes (SCs) to ensure a more equitable distribution of reservation benefits among all constituent communities. This grassroots movement sought to highlight the disparities within the SC category and demand justice for underrepresented communities.

4. A significant aspect of the movement was the reclamation of the term "Madiga" which had been used pejoratively. By adopting "Madiga" as his surname, he transformed it into a symbol of pride and resistance. The movement also embraced the "Dandora," a traditional announcement made using the Dappu (a leather drum), as a powerful emblem of their struggle. This cultural symbolism resonated deeply within the community and amplified their call for justice

5. Shri Madiga has been a vocal advocate for various social causes. In 2007, he founded the "Vikalangula Hakkula Porata Samithi" to champion the rights of persons with disabilities. He also took up the issues of children affected with cardiac diseases. His activism irrespective of caste, creed, religion, and all other identities led to the implementation of Arogyasri (Health Insurance scheme) and Monthly pensions for the disabled in the erstwhile Andhra Pradesh. He has also been instrumental in campaigns advocating for increased pensions for widows and single women, expanded ration rice quotas and medical assistance for children with heart ailments. His multifaceted activism underscores his commitment to uplifting all marginalized sections of society.

6. Under Shri Madiga's leadership, the MRPS organized numerous protests, dharnas and rallies bringing national attention to the issue of SC subcategorization. In 2008, he undertook a hunger strike to emphasize the urgency of their demands. His relentless advocacy played a pivotal role in the eventual acceptance of SC sub-categorization by both central and state governments. In August 2024, the Supreme Court of India ruled in favour of allowing states to sub-classify Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) to ensure that reservation benefits reach the most disadvantaged groups.

7. Shri Madiga's relentless struggle from a grassroots activist to a nationally recognized leader exemplifies the power of resilience and dedication. His life's work has not only brought about tangible policy changes but has also inspired countless individuals to advocate for their rights and dignity.

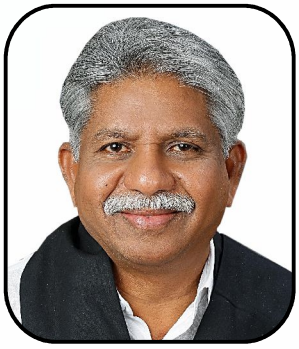

श्री मंदा कृष्ण मादिगा

श्री मंदा कृष्ण मादिगा तेलंगाना के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने मादिगा समुदाय और हाशिए पर जी रहे अन्य वंचित समुदायों के लिए सामाजिक न्याय हेतु जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे अनुसूचित जाति उप–वर्गीकरण संबंधी ऐतिहासिक निर्णय का मार्ग प्रशस्त हुआ।

2. 7 जुलाई, 1965 को तेलंगाना के हनमकोंडा के न्यू श्यामपेट में मादिगा समुदाय में जन्मे, श्री मादिगा का समुदाय परंपरागत रूप से चमड़े के काम करता था और अन्य सीमांत व्यवसायों से जुड़ा हुआ था । उन्होंने अपने समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों और व्यवस्थागत भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। 1980 के दशक की शुरुआत में, वारंगल, तेलंगाना में इनका उदय प्रमुख जाति–विरोधी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हुआ, इन्होंने निचली जातियों पर अत्याचार करने वाले प्रमुख जाति के लोगों का विरोध किया। इन्होंने कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से हाशिए पर जी रहे दलित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने का विकल्प चुना।

3. विशेषतः मादिगा और अन्य उप–जातियों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने में व्यापक दलित आंदोलन की अक्षमता से निराश होकर, श्री मादिगा ने अनुभव किया कि इसके लिए लक्ष्य केंद्रित आंदोलन की आवश्यकता है और इसी के परिणामस्वरूप वर्ष 1994 में मादिगा आरक्षण पोराटा समिति (एमआरपीएस) की स्थापना हुई। एमआरपीएस की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जातियों (एससी) के उप–वर्गीकरण की वकालत करना था जिससे कि सभी घटक समुदायों के बीच आरक्षण संबंधी लाभों का अधिक न्यायसंगत संवितरण सुनिश्चित किया जा सके। इस जमीनी स्तर के आंदोलन का उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर असमानताओं को उजागर करना और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए न्याय की मांग करना है।

4. मादिगा नाम का उपयोग अपमानजनक रूप से किया जाता था और इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पहलू "मादिगा" नाम से जुड़ा सम्मान वापस दिलाना था। "मादिगा" को अपने उपनाम के रूप में अपनाकर, उन्होंने इसे गौरव और प्रतिरोध के प्रतीक का रूप दे दिया। इस आंदोलन में संघर्ष के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में "दंडोरा" को भी अपनाया गया, जिसमें पारंपरिक घोषणा के लिए डप्पू (चमड़े का ड्रम) का उपयोग किया जाता था। इस सांस्कृतिक प्रतीक की गूंज पूरे समुदाय के भीतर अंदर तक उठी और न्याय के आह्वान को और बल मिला।

5. श्री मादिगा विभिन्न सामाजिक आंदोलन के मुखर समर्थक रहे हैं। वर्ष 2007 में, उन्होंने दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा के लिए "विकलांगुला हक्कुला पोराता समिति" की स्थापना की। उन्होंने हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों के मुद्दों को भी उठाया। जाति, पंथ, धर्म और अन्य सभी पहचानों से परे इनकी सक्रियता के कारण तत्कालीन आंध्र प्रदेश में दिव्यांगों के लिए आरोग्यश्री (स्वास्थ्य बीमा योजना) और मासिक पेंशन का कार्यान्वयन हो पाया। इन्होंने विधवाओं और अकेली रहने वाली महिलाओं के लिए बढ़ी हुई पेंशन, विस्तारित राशन चावल कोटा और हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए चिकित्सा सहायता का समर्थन करने वाले अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी बहुमुखी सक्रियता हाशिए पर जीवनयापन कर रहे समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

6. श्री मादिगा के नेतृत्व में, एमआरपीएस ने कई विरोध प्रदर्शन, धरने और रैलियाँ आयोजित कीं, जिसने एससी उप–वर्गीकरण के मामले में राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 2008 में, उन्होंने भूख हड़ताल की जिससे कि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाए। इनकी अथक वकालत ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा एससी उप–वर्गीकरण को अंततः स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगस्त 2024 में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को उप–वर्गीकृत करने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित समूहों तक पहुँचे।

7. श्री मादिगा का एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नेता बनने तक का अथक संघर्ष प्रतिरोध क्षमता और समर्पण की शक्ति का उदाहरण है। इनके काम से न केवल ठोस नीतिगत बदलाव को प्रेरणा मिली है, बल्कि अनगिनत व्यक्तियों को अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने के लिए भी प्रेरित किया है।